

**भारत सरकार**  
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**तारांकित प्रश्न सं. 75**  
**बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम**

75. श्री बिद्युत बरन महतो: श्री लुम्बाराम चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) शहरी क्षेत्रों में रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के उद्देश्यों, कार्यान्वयन ढांचे और प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) दस राज्यों में से पहले तीस शहरों के चयन के मानदंड क्या हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों, विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और राज्य नोडल एजेंसियों की क्या भूमिकाएं परिभाषित की गई हैं,
- (ग) इसमें भागीदारी करने वाले शहरों को समर्पित दलों की तैनाती सहित कितनी तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और नीतिगत सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है,
- (घ) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर-पूर्व के राज्यों को भी प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या चयन किए गए पहले तीस शहरों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किन्हीं शहरों को भी शामिल किया गया है; और
- (च) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में अब तक हुई प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**  
**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

- (क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

## विवरण

### **‘सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 04.02.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 75 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के सहयोग से जून 2025 में सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (CAP) की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के अंतर्गत देशभर के 100 शहरों में दो चरणों में रूफटॉप सोलर लगाने के कार्य में तेजी लाना है। प्रारंभिक चरण में, 10 राज्यों के 30 शहरों का चयन मानदंडों के आधार पर किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

- शहरी जनसंख्या का आकार और पीएमएसजी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन;
- रूफटॉप सौर संभाव्यता और अपनाने के मौजूदा स्तर;
- डिस्कॉम और राज्य नोडल एजेंसियों (SNA<sub>s</sub>) की तैयारी और क्षमता; तथा
- राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (ULB<sub>s</sub>) की सक्रिय भागीदारी और कार्यान्वयन में सहयोग करने की इच्छा।

इस कार्यान्वयन ढांचे में त्रि-स्तरीय समन्वित संरचना अपनाई गई है, जिसमें एमएनआरई, समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा, समन्वय और निगरानी प्रदान करता है; राज्य सरकारें और राज्य नोडल एजेंसियां नीति समर्थन और डिस्कॉमों के साथ समन्वय के माध्यम से अपनाना सुविधाजनक बनाती हैं; और शहरी स्थानीय निकायों (ULB<sub>s</sub>) द्वारा शहरी स्तर पर जागरूकता फैलाई जाती है, सुविधाजनक बनाया जाता है और क्षमता निर्माण गतिविधियों को वास्तविक रूप से संचालित किया जाता है।

सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम को लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से रूफटॉप सौर अपनाने के लिए शहर-विशिष्ट अवरोधों को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें समर्पित सिटी एक्सेलेरेटर सेलों की स्थापना, डिस्कॉमों, राज्य नोडल एजेंसियों, वेंडरों और यूएलबी के साथ हितधारक समन्वय को मजबूत करना, नियमित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों तथा जागरूकता अभियानों, और बेहतर सुविधा तथा शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।

(घ) सिटी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के प्रारंभिक प्रथम 30 शहरों में असम के तीन शहर अर्थात गुवाहाटी, बारपेटा और डिब्रूगढ़ को शामिल किया गया है।

(ड.): मध्य प्रदेश राज्य के लिए भोपाल, जबलपुर, सतना और इंदौर को शामिल किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शहर को सीएपी के प्रारंभिक चरण के प्रथम 30 शहरों में शामिल नहीं किया गया है।

(च): मध्य प्रदेश राज्य में कैप के तहत, सिटी एक्सेलेरेटर सेल्स ने पीएमएसजी: एमबीवाई के कार्यान्वयन में सहयोग के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राज्य के डिस्कॉम, नगर पालिकाएं, बैंक, आरटीएस वेंडर और अन्य हितधारकों के साथ संरचित संपर्क स्थापित किए। ये गतिविधियाँ योजना के दिशानिर्देशों, भूमिकाओं और प्रक्रियाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, एजेंसियों के बीच समन्वय सुधारने, और बैठकों व क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं का पता लगाने पर केंद्रित हैं।

\*\*\*\*\*